गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 141
दि. 20.09.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहाः "प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूँ। संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा।

आज गुजरात में ढट मोदी, 34200 करोड़ की देंगे सौगात, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और 34 हजार 200 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। उनका ये दौरा नेवी के क्षेत्र में अहम है। इंदिरा डॉक पर प्रधानमंत्री मोदी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। अपने इस गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी धोलेरा का एरियल सर्वे भी करेंगे।

भावनगर के कलेक्टर मनीष कुमार बंसल ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर को भावनगर आएंगे। वह जवाहर मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, गुजरात समुद्री बोर्ड और अन्य राज्यों के समुद्री बोर्ड की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्र से संबंधित एक नीति की भी शुरूआत करने का कार्यक्रम है।" उन्होंने बताया कि इस दौरान इस क्षेत्र की सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।"

धोलेरा का हवाई सर्वे करेंगे

पीएम मोदी भावनगर में सुबह लगभग 10:30 बजे 34,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।

इसके बाद, वह धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दोपहर लगभग 1:30 बजे, वह एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिख प्रतिनिधिमंडल के प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्यों से भेंट की

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अत्यंत पवित्र एवं अमूल्य पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा एवं उचित प्रदर्शन के संबंध में सिफारिशें प्राप्त की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिख प्रतिनिधिमंडल के प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया, जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अत्यंत पवित्र एवं अमूल्य पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा और उचित प्रदर्शन के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपीं। श्री मोदी ने कहा कि ये पवित्र अवशेष 'जोरे साहिब' जितने महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, उतने ही गौरवशाली सिख इतिहास और राष्ट्र के सांस्कृतिक लोकाचार का भी हिस्सा हैं। श्री मोदी ने कहा, "ये पवित्र अवशेष आने वाली पीढ़ियों को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिखाए गए साहस, नेकी, न्याय और सामाजिक सद्भाव के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे।"

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को एक एक्स पोस्ट में दिए गए उत्तर में श्री मोदी ने कहाः मुझे सिख प्रतिनिधिमंडल के प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हुई, जिन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अत्यंत पवित्र और अमूल्य पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा और उचित प्रदर्शन के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंपी।

'जोरे साहिब' जैसे महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण पवित्र अवशेष हमारे देश के सांस्कृतिक लोकाचार के साथ-साथ गौरवशाली सिख इतिहास का भी हिस्सा हैं।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) की 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक चेन्नई में संपन्न

(जीएनएस)।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई), जनपथ, नई दिल्ली और तमिलनाडु अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान, चेन्नई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अभिलेखपालों की राष्ट्रीय समिति (एनसीए) की दो दिवसीय 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक 19 सितंबर 2025 को चेन्नई स्थित तमिलनाडु अभिलेखागार में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। चेन्नई ने चौथी बार एनसीए बैठक की मेजबानी की, जो भारत की अभिलेखीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाता है।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन तमिलनाडु सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. गोवी चेझियान की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों में राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक एवं एनसीए के अध्यक्ष श्री संजय रस्तोगी, आईएएस; तमिलनाडु अभिलेखागार प्रधान सचिव/आयुक्त एवं एनसीए के स्थानीय सचिव श्री हर सहाय मीणा, आईएएस; राष्ट्रीय अभिलेखागार की अपर महानिदेशक सुश्री नेहा बंसल, आईएएस; तमिलनाडु उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. डीपी शंकर, आईएएस; तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार के उपनिदेशक (कार्यवाहक) एवं एनसीए के सदस्य सचिव श्री नौरोइबाम राजू सिंह शामिल थे।

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. गोवी चेझियान ने तमिलनाडु सरकार की अभिलेखीय संरक्षण की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए बताया कि पिछले वर्ष जापानी टिशू मेंडिंग तकनीक को अपनाने हेतु 10 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्रधानमंत्री ने प्रिंस चार्ल्स तृतीय द्वारा उपहार में दिया गया कदम्ब का पौधा लगाया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर आज कदम्ब का एक पौधा लगाया, जो उन्हें प्रिंस चार्ल्स तृतीय ने उपहार में दिया था। श्री मोदी ने कहा, "पर्यावरण और स्थिरता के प्रति वे बेहद भावुक हैं, और यह विषय हमारे विचार-विमर्श में भी शामिल होता है।"

श्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा : 7, लोक कल्याण मार्ग पर आज सुबह, एक कदम्ब का पौधा लगाया, जो प्रिंस चार्ल्स तृतीय द्वारा उपहार में दिया गया था। वे पर्यावरण और स्थिरता के प्रति बेहद भावुक हैं, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम अपने विचार-विमर्श के दौरान चर्चा करते हैं।"

आयुर्वेद दिवस 2025 : विषय 'जन-जन के लिए आयुर्वेद' : केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस 2025 के लिए प्रेसवार्ता को संबोधित किया

(जीएनएस)।

आयुष मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (एनएमसी), नई दिल्ली में आयुर्वेद दिवस 2025 के लिए पूर्वावलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने मीडिया को संबोधित किया और 10वें आयुर्वेद दिवस के लिए नियोजित प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला। यह दिवस 23 सितंबर 2025 को गोवा के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) में मनाया जाएगा।

अपने संबोधन में श्री जाधव ने एक समग्र, साक्ष्य-आधारित और पर्यावरण की दृष्टि से सतत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के रूप में आयुर्वेद की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा विज्ञान से कहीं अधिक है-यह जीवन का एक तरीका है जो व्यक्तियों का उनके पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आयुष पर पहले अखिल भारतीय एनएसएसओ सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए श्री जाधव ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में आयुर्वेद की व्यापक स्वीकृति पर जोर दिया, जहां यह सबसे अधिक प्रचलित उपचार प्रणाली बनी हुई है।

श्री जाधव ने सूचित किया कि केंद्र सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के लिए एक निश्चित वार्षिक तिथि के रूप में अधिसूचित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे इसे एक सार्वभौमिक कैलेंडर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय - "जन-जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद" - वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कल्याण के लिए एक सतत, एकीकृत समाधान के रूप में आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

श्री जाधव ने यह भी घोषणा की कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद दिवस 2025 पर कई जन-केंद्रित पहलें शुरू की जाएगी।

इनमें छात्रों के लिए "कल्याण के लिए छोटे कदम", झूठे विज्ञापनों का मुकाबला करने के लिए "गुमराह को राह दिखाएं", "मोटापे के लिए आयुर्वेद आहार" जैसे जागरूकता अभियान, साथ ही पौधों और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद पर कार्यक्रम भी शामिल हैं। विशेष ध्यान "कैंसर उपचार में समन्वय", "आयुर्वेद का डिजिटल रूपान्तरण" और "संहिता से संवाद", जो धरती के कल्याण हेतु मीडिया साझेदारी है - पर भी दिया जाएगा।

आयुर्वेद दिवस की यात्रा का स्मरण करते हुए श्री जाधव ने बताया कि 2016 से इसकी शुरूआत हुई और 2024 संस्करण में 150 से अधिक देशों ने भागीदारी की। उन्होंने 9वें आयुर्वेद दिवस की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिनमें एआईआईए के द्वितीय चरण का उद्घाटन, आयुर्वेद में चार उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और प्रधानमंत्री द्वारा "देश का प्रकृति परीक्षण अभियान" का शुभारंभ शामिल है। उन्होंने आगे सूचित किया कि 12,850 करोड़ रुपये के निवेश से आयुर्वेद की समग्र स्वास्थ्य सेवा में भूमिका को और मजबूत किया गया है।

इस अवसर पर एआईआईए के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति ने आगामी समारोह का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 10वें आयुर्वेद दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, डिजिटल अभियान, अंतर-मंत्रालयी सहयोग, राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 तथा उप-विषयों जैसे - मोटापा रोकथाम, कैंसर जागरूकता, छात्र पहुंच, पशु एवं पौधा स्वास्थ्य और डिजिटल एकीकरण -पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। MyGov और MyBharat प्लेटफॉर्म पर "आई सपोर्ट आयुर्वेद" जैसी पहलों के माध्यम से जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज गोंडा में वृक्ष उत्पादक मेले का उद्घाटन किया

वृक्षों की उत्पादकता समाज और पर्यावरण के लिए जीवन रेखा है; समुदाय को भावी पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए: श्री के.वी. सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित जिला पंचायत सभागार में आईसीएफआरई-पारिस्थितिक पुनरुद्धार केंद्र, प्रयागराज द्वारा आयोजित वृक्ष उत्पादक मेले का उद्घाटन किया।

उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वृक्षों की उत्पादकता केवल कृषि भूमि या आय सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण, दोनों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा, "रोपा गया प्रत्येक पेड़ स्वच्छ वायु, जल सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देता है। गांवों में बढ़ती हरियाली पक्षियों और अन्य प्रजातियों सहित जैव विविधता के संरक्षण में भी मदद करती है।" मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि किसान और समुदाय अपने खेतों, बंजर भूमि और चरागाहों पर वृक्षारोपण करने के लिए प्रतिबद्ध हों, तो इससे परिवारों की समृद्धि, क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मानव सभ्यता की वनों पर ऐतिहासिक निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि अनियंत्रित दोहन, तीव्र औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण दुनिया भर में अभूतपूर्व वनों की कटाई हुई है। उन्होंने कहा, "वनों और भूमि संसाधनों का क्षरण अब एक बड़ी चुनौती है।"

युवक ने सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, कहा- मैं आपको गोली से मार दूंगा; पुलिस पहुंची घर तो...

(जीएनएस)।

मथुरा के मांट में सुनीत नामक एक युवक ने नशे की हालत में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी। पारिवारिक विवादों से परेशान होकर उसने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वह छत पर चढ़ गया और फायरिंग की। बाद में पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा के फरह में मुख्यमंत्री के जाने के बाद इंटरनेट मीडिया में एक युवक का खुद की कनपटी पर पिस्टल रखकर सीएम को जान से मारने का वीडियो वायरल हो गया। जानकारी जुटाकर पुलिस उसके पास पहुंची तो युवक तीन मंजिल मकान की छत पर चढ़ गया। पुलिस पर पिस्टल से तीन फायर झोंक दिए। तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद मांट थाना प्रभारी ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनकर उसे पीछे से दबोच लिया। युवक नशेड़ी है। पारिवारिक विवाद के कारण वह मानसिक रूप से अवसाद में चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मांट थाना क्षेत्र के नगला हरदयाल मजरा जाबरा निवासी सुनीत उर्फ गटुआ का ताऊ के बेटे रामप्रकाश से एक स्कूल की जमीन का विवाद चला आ रहा है। रामप्रकाश ने सुनीत की मां से बैनामा कराया था। सुनीत का आरोप है कि मां से धोखे से बैनामा कराया गया है।

जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद चला आ रहा है। उसने सीएम पोर्टल से लेकर कई अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते सुनीत मानसिक परेशान रहने लगा और अधिक नशा करने लगा।

गुरुवार रात को सुनीत ने नशे में एक वीडियो बनाया। 21 सेकंड के वीडियो में उसने अपनी कनपटी में पिस्टल रखकर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दे दी। गुरुवार को फरह कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री के जाने के बाद इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित हो गया।

प्रधानमंत्री के साथ सिख संगत की बैठक में प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का सुंदर गायन प्रस्तुत किया

प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने आज सिख संगत के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा, "सिख संगत के साथ बैठक में प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का एक सुंदर गायन प्रस्तुत किया।"एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहाः सिख संगत के साथ बैठक में प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का एक सुंदर गायन प्रस्तुत किया...

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

क्या नेपाल को नया रास्ता दिखा पाएंगी कार्की?

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक विशेषाधिकारों पर गुस्से से उपजे इस आंदोलन ने दिखा दिया है कि जनता अब केवल नाराज नहीं है बल्कि वैकल्पिक राजनीति की तलाश में है। सुशीला काका का ईमानदार और निभाक अतीत युवाओं के लिए आशा का प्रतीक है लेकिन उन्हें यह उम्मीद ठोस नीतिगत कदमों के जरिए पूरी करनी होगी, केवल प्रतीकात्मक बदलाव अब पर्याप्त नहीं होंगे। नेपाल की राजनीति का परिदृश्य आज अभूतपूर्व हलचल और बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जेन-जी की हिसक बगावत के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंची सुशीला काका का उदय केवल एक व्यक्ति विशेष की कहानी नहीं है बल्कि यह उस पीढ़ी का सार्वजनिक घोषणापत्र है, जिसने तय कर लिया कि अब पुरानी राजनीति की अपंग परंपराओं से मुक्ति पाकर एक नया नेपाल गढ़ना ही उनका ध्येय है। नेपाल बार-बार बदलती सरकारों, टूटते गठबंधनों और भ्रष्टाचार की दलदल में पंसा रहा है लेकिन इस बार जो हुआ है, वह केवल सत्ता परिवर्तन का प्रसंग नहीं है बल्कि विचार और आचरण दोनों की निर्णायक परीक्षा है। केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का कदम चिगारी साबित हुआ, जिसने युवाओं की उस आक्रोशित धारा को धधकती ज्वाला में बदल दिया, जिसे रोका नहीं जा सकता था। इस विस्फोट ने न केवल ओली को सत्ता से बेदखल किया बल्कि नेपाली राजनीति को गहरे आत्ममंथन की स्थिति में भी ला खड़ा किया। इसी अशांत वातावरण में पहली बार देश को एक ऐसी प्रधानमंत्री मिली हैं, जिनकी पहचान ईमानदारी, साहस और न्यायप्रियता है। सुशीला काका का प्रधानमंत्री पद पर आसीन होना एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक घटना है। अब तक पुरुष-प्रधान राजनीति के घेरे में वैद इस देश की सत्ता के सर्वोच्च पद तक एक महिला की पहुंच केवल एक पद के बदलाव का चिन्ह नहीं है बल्कि यह गहरे सामाजिक बदलाव का संकेत भी है लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण के भीतर अनेक विकट चुनौतियां छिपी हैं। नेपाल की सड़कों पर उबलते गुस्से को शांत करना, राज्य को हिसा की आग से बाहर निकालना और राष्ट्रीय स्थिरता बहाल करना वर्तमान अंतरिम प्रधानमंत्री की पहली और सबसे कठिन परीक्षा है। देश एक अत्यंत मुश्किल मोड़ पर खड़ा है, जहां लोकतांत्रिक आकांक्षाएं और जनता का विस्फोटित असंतोष, दोनों एक साथ सरकार की परीक्षा ले रहे हैं। जेन-जी की पांच शर्तो को मानना इस बात की निशानी है कि सत्ता का संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पुरानी राजनीति अब मान्य नहीं है। संसद के विघटन से लेकर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्णय इस बात का प्रमाण है कि नई अंतरिम सरकार जनता की आंखों से बचकर कार्य नहीं कर सकती। सेना और नागरिक प्रतिनिधियों के मिश्रित शासन मॉडल की शर्त इस ओर संकेत करती है कि युवा अब केवल नारेबाजी से संतुष्ट नहीं होगा बल्कि वह एक ठोस और पारदशा सिस्टम की मांग कर रहा है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार निवारक आयोग और हिसा की जांच संबंधी न्यायिक आयोग का गठन काका सरकार का पहला कदम बना। असली कसौटी यह होगी कि यह जांच और आयोग केवल औपचारिकता साबित न हों बल्कि सचमुच दोषियों को बेनकाब कर सवें। नेपाल के वर्तमान संकट को समझने के लिए बीते सात दशकों के इतिहास को देखना जरूरी है। यहां राजशाही से साम्यवाद और फिर लोकतंत्र तक के सभी प्रयोग हो चुके हैं। हर बार जनता को उम्मीदें दिखाई गईं लेकिन हर बार वे उम्मीदें ताश के पत्तों की तरह ढ़ह गईं। राजशाही निरंवुशता और पिछड़ेपन का प्रतीक रही, साम्यवाद गुटबाजी और भ्रष्टाचार में डूब गया और लोकतंत्र केवल चुनावी राजनीति तक सिमटकर रह गया। इसने जनता को निराशा के सिवाय वुछ नहीं दिया। यही कारण है कि युवा पीढ़ी आज किसी भी ह्यवादह्न पर भरोसा नहीं करती। उसका एकमात्र आग्रह है पारदर्शिता, जवाबदेही और अवसर। यही लोकतंत्र की नई कसौटी है। सुशीला काका के अतीत को देखें तो स्वयं उनके जीवन की यात्रा भी संघर्ष और साहस का परिचय देती है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मिले, खेतों में जाकर नुकसान का जायजा लिया

बाढ़ प्रभावित किसानों से बोले कृषि मंत्री- आपदा के इस क्षण में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है

प्रभावित लोगों के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने किए राहत के कई ऐलान, बोले- किसान सम्मान निधि की राशि जल्द जारी होगी

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कामगारों को मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त काम मिलेगा- श्री शिवराज सिंह चौहान

फसल से लेकर जान-माल की हानि की होगी क्षतिपूर्ति- श्री शिवराज सिंह चौहान

(जीएनएस)।

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने ग्राम बडयाल ब्राह्मण, आरएसपुरा, जम्मू में बाढ़ प्रभावित किसान भाई-बहनों के साथ संवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा से किसानों को बाहर निकालेगी।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि गृह मंत्रालय, जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय सहित सभी विभागों की टीमें यहां आई हैं। सभी टीमों ने सर्वे किया है और टीमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। नुकसान का आंकलन चल रहा है। राज्य सरकार का ज्ञापन आएगा, इसके बाद हम राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ काम ऐसे हैं जो राज्य सरकार को करना है। हम आपदा में कोई राजनीति नहीं करेंगे। पहला काम है, गरीबों को संकट से बाहर करना। रेत के मामले में राज्य के स्तर पर फैसला कर लेना चाहिए कि जिसका खेत, उसकी रेत। रेत बची है, तो वही किसानों को दे दी जाए, खनन के नियम लागू न हों। किसान अपने-अपने खेतों की रेत बेचें, यह व्यवस्था होनी चाहिए।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान हैं, उनको हम लागू करेंगे। राज्य सरकार को केंद्र सरकार राशि देती है, जिसमें 75% हिस्सा केंद्र और 25% राज्य सरकार का होता है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के पास लगभग 2,499 करोड़ रुपये हैं। उसका उपयोग सरकार करेगी। इसके अलावा जो जरूरत होगी, केंद्र सरकार हरसंभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भगवान न करे कि ऐसा हो लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। दिव्यांग होने पर भी सहायता राशि दी जाती है।

श्री चौहान ने कहा कि गाद निकालना हो तो 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। पहाड़ खिसकने से नुकसान होने पर सीमांत किसानों को 47 हजार रुपये देने का प्रावधान है। मिर्च और धान जैसी फसल का नुकसान हुआ है, बीमित किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। राहत की राशि के अलावा हम फसल बीमा योजना की राशि देंगे। सब्जी और बागवानी फसल के लिए सिंचित क्षेत्र में 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है, कृषि वानिकी के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। ये राशि राज्य सरकार के द्वारा टी जायेगी। दुधारू पशु के नुकसान पर 37500 रुपये, घोड़ा और बैल के नुकसान पर 32 हजार रुपये, बछड़ा, टट्टू और खच्चर के नुकसान के लिए 20 हजार रुपये के मुआवजे का प्रावधान है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नहर क्षतिग्रस्त हैं, तो भी बांध के लिए भी राज्य सरकार केंद्र सरकार से बात करे। कई जगह मकान टूट गए हैं। श्री शिवराज सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि 1 लाख 30 हजार रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए दिए जाएंगे। शौचालय के अलग और मनरेगा की मजदूरी के लिए 40 हजार रुपये ग्रामीण विकास विभाग देगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5,101 मकान की जानकारी आई है, मैं यहाँ से जाते ही इसकी स्वीकृति दे दूंगा। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों का काम यहां बहुत अच्छा है। यहां बहनों को नुकसान हुआ होगा। हम उसके लिए 76 करोड़ रुपये की राशि जारी करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सड़कों के लिए राज्य सरकार से ज्ञापन मिलने के बाद उस संबंध में भी हम व्यवस्था करेंगे। मनरेगा की मजदूरी 100 दिन की होती है, हम राज्य सरकार से अनुरोध करेंगे कि 150 दिन की मजदूरी दी जाए। श्री चौहान ने कहा कि सीमा पर रहने वाले कई किसान खेती तो कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वामित्व नहीं है। अगर राज्य सरकार प्रमाणित कर दें, तो उन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्र बना दिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की एक किश्त हम तुरंत जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में डालेंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में जाकर खराब फसलों का निरीक्षण किया। किसानों की समस्या सुनी और हरसंभव मदद का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि संकट बड़ा है और जब फसलें बर्बाद होती हैं तो केवल फसलें बर्बाद नहीं होती हैं। किसान की जिंदगी बर्बाद होती है, उनके बच्चों का भविष्य तबाह होता है लेकिन किसान दुःखी न हों, सरकार उनके साथ है। श्री चौहान ने कहा कि आज यहां मैं अकेला नहीं आया हूं बल्कि मेरा पूरा विभाग आया है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी यहां की स्थिति पर चिंतित हैं। आज स्वयं मैंने देखा है कि जहां कभी फसलें लहलहा रही थीं वहां रेत के टीले जम चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि खेतों में चार से पांच फीट रेत के ढेर लग चुके हैं। रेत के अंदर फसलें दबकर बर्बाद हो गई हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल एक बार खराब हो गई तो कई सालों तक किसान उससे उबर नहीं पाते हैं। आज उस दर्द को मैंने खेतों में जाकर देखा है। बाढ़ में पशु बह गए हैं। नुकसान बड़ा है और आपदा गहरी है और लोगों के दर्द भी गहरे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम इस स्थिति से जरूर उबरेंगे और किसानों के खेतों में फिर से समृद्धि और खुशहाली आएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मशीनरी के लिए जीएसटी सुधारों पर महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी के लिए नवीनतम जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। ट्रैक्टर एवं मशीनीकरण संघ (टीएमए), कृषि मशीनरी निमार्ता संघ (एएमएमए), अखिल भारतीय कंबाइन निमार्ता संघ (एआईसीएमए) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीटीएआई) सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत और वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

श्री चौहान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जीएसटी दरों में कटौती के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और चर्चा का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि कृषि मशीनरी पर जीएसटी, जो पहले 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत थी, अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि इस कटौती से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है, जिसके लिए उत्पादकता बढ़ाने और लागत कम करने, दोनों की आवश्यकता है और दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान, मशीन निमार्ता संघों के सभी प्रतिनिधियों को बताया गया कि 22 सितंबर से लागू जीएसटी की घटी हुई दरें पूरी पारदर्शिता के साथ किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। श्री चौहान ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी एक बड़ा कदम है, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बाद में, कीमतों में हुई उल्लेखनीय कमी की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा:

ए 35 एचपी ट्रैक्टर अब 41,000 रुपये सस्ता मिलेगा

ए 45 एचपी ट्रैक्टर अब 45,000 रुपये सस्ता मिलेगा

ए 50 एचपी ट्रैक्टर अब 53,000 रुपये सस्ता मिलेगा

ए 75 एचपी ट्रैक्टर अब 63,000 रुपये सस्ता मिलेगा

बागवानी और निराई-गुड़ाई में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टरों की कीमत भी कम हो जाएगी। 4-पंक्ति वाला धान रोपने वाला यंत्र अब 15,400 रुपये सस्ता हो जाएगा, जबकि 4 टन प्रति घंटे की क्षमता वाला बहु-फसल थ्रेशर 14,000 रुपये सस्ता हो जाएगा। 13-एचपी पावर टिलर की कीमत भी 11,875 रुपये कम हो जाएगी।

कीमतों की कटौती में ये भी शामिल हैं:

पावर वीडर (7.5 एचपी): 5,495 रुपये सस्ता

ट्रेलर (5 टन क्षमता): 10,500 रुपये सस्ता

बीज-सह-उर्वरक ड्रिल (11 टाइन): 3,220 रुपये सस्ता

बीज-सह-उर्वरक ड्रिल (13 टाइन): 4,375 रुपये सस्ता

हार्वेस्टर कंबाइन कटर बार (14 फीट): 1,87,500 रुपये सस्ता

स्ट्रॉ रीपर (5 फीट): 21,875 रुपये सस्ता

सुपर सीडर (8 फीट): 16,875 रुपये सस्ता

हैप्पी सीडर (10 टाइन): 10,625 रुपये सस्ता

रोटावेटर (6 फीट): 7,812 रुपये सस्ता

चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्रवाई जारी चुनाव आयोग ने 474 और आरयूपीपी को सूची से हटाया

359 और आरयूपीपी को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू

(जीएनएस)।

देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/आरयूपीपी) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के साथ पंजीकृत हैं।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत, किसी भी संगठन को एक बार राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत होने पर, प्रतीक, कर छूट आदि जैसे कुछ विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त होते हैं।

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिदेशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई पार्टी 6 वर्षों तक लगातार चुनाव नहीं लड़ती है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।

चुनावी प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने की एक व्यापक और सतत रणनीति के तहत, निर्वाचन आयोग 2019 से लगातार 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की आवश्यक शर्त को पूरा करने में विफल रहे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास कर रहा है।

इस प्रक्रिया के पहले चरण में, ईसीआई ने 9 अगस्त, 2025 को 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया था।

इसी क्रम में, दूसरे चरण में, चुनाव आयोग ने 18 सितंबर, 2025 को 474 आरयूपीपी को चुनाव आयोग द्वारा लगातार 6 वर्षों तक आयोजित चुनावों में भाग न लेने के आधार पर सूची से हटा दिया। इस प्रकार, पिछले 2 महीनों में 808 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया गया है। (अनुलग्नक-ए)

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, 359 ऐसे आरयूपीपी की पहचान की गई है , जिन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अर्थात 2021-22, 2022-23, 2023-24) में अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए हैं और चुनाव तो लड़े हैं, लेकिन चुनाव व्यय रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। ये देश भर के 23 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। (अनुलग्नक-बी)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी पक्ष को अनुचित रूप से सूची से बाहर न किया जाए, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इन आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा सुनवाई के माध्यम से पक्षों को अवसर दिया जाएगा।

ईसीआई सीईओ की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी आरयूपीपी को सूची से हटाने पर चुनाव आयोग अंतिम निर्णय लेता है।

मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री डॉ. अविनाश रामतोहुल ने दिल्ली में सी-डॉट परिसर का दौरा किया

सी-डॉट ने गणमान्य लोगों के समक्ष स्वदेशी उन्नत दूरसंचार समाधान एवं अन्य प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया

मंत्री ने सी-डॉट की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एवं सेल प्रसारण समाधान, साइबर सुरक्षा और संवाद में गहरी रुचि व्यक्त की

(जीएनएस)।

मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री, महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल ने आज दिल्ली में सी-डॉट परिसर का दौरा किया। उन्होंने सी-डॉट की पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं सेल प्रसारण समाधान में गहरी रुचि व्यक्त की जो आपदाओं के दौरान नागरिकों की जान बचाने में मदद करती हैं। उन्होंने सी-डॉट द्वारा प्रस्तुत साइबर सुरक्षा एवं संवाद समाधान का भी अवलोकन किया।

सी-डॉट के सीईओ, डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने मॉरीशस प्रतिनिधिमंडल के समक्ष प्रमुख अनुप्रयोगों का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जिसमें विविध दूरसंचार उत्पाद पोर्टफोलियो/समाधान शामिल हैं, जिसमें आईटीयू सीएपी प्रोटोकॉल और सेल प्रसारण समाधान का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन समाधान एवं सुरक्षा संचालन केंद्र (अंतिम बिंदुओं को कवर करते हुए दुर्भावनापूर्ण खतरों एवं हमलों का वास्तविक समय में पता लगाना और उनका शमन करना), क्वांटम कुंजी वितरण, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी एवं संवाद, एक सुरक्षित चैट और कॉलिंग एप्लिकेशन जैसे सुरक्षा समाधान शामिल हैं। अन्य समाधान जैसे 4जी कोर और 4जी आरएएन; 5जी कोर और 5जी आरएएन; ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट और एक्सेस समाधान; स्विचिंग एवं रूटिंग समाधान उनके संबंधित कार्यात्मक पहलुओं एवं उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए मुख्य रूप से शामिल है।

अपनी यात्रा के दौरान महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल ने सी-डॉट के प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली एवं सेल प्रसारक (सीबी) समाधान की सराहना की और भारत में इसके कार्यान्वयन को मान्यता दी। उन्होंने कहा कि "यह समाधान अत्यंत लाभकारी है और यह सभी नागरिकों, विशेषकर मछुआरा समुदाय, के जीवन को सुरक्षित करने में मदद करेगा। इस सहयोग ने आपातकालीन चेतावनी एवं दूरसंचार नवाचार में गहन और दूरदर्शी सहयोग के लिए मंच प्रदान किया है। मैं भारत के साथ इस सहयोग की सराहना करता हूं क्योंकि यह दर्शाता है कि दूरसंचार में विश्वसनीय साझेदारी कैसे नवाचार एवं राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान कर सकती है।"

मंत्री के साथ मॉरीशस टेलीकॉम के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष श्री शरत दत्त लालाह भी मौजूद थे। उन्होंने सी-डॉट के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की सराहना की और पारस्परिक लाभ के लिए भविष्योन्मुखी एवं अत्याधुनिक दूरसंचार समाधानों के विकास पर व्यापक सहयोग की बात की।

सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने कहा, "मॉरीशस के साथ हमारा सहयोग हमारी इस साझा मान्यता को दर्शाता है कि प्रौद्योगिकी को राष्ट्रों के बीच विकास को बढ़ावा देने वाले समाधानों के सह-निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दशार्ती हैं।"

सी-डॉट, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है जो स्वदेशी, सुरक्षित दूरसंचार समाधान विकसित करने में सक्रिय रूप से काम करता है। पिछले चार दशकों में सी-डॉट भारत की दूरसंचार क्रांति में सबसे अग्रणी रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करना, महत्वाकांक्षी भारतनेट (एनओएफएन) परियोजना को शक्ति प्रदान करना और साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, 4जी/5जी, अगली पीढ़ी के नेटवर्क, एआई, नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, आईओटी/एम2एम अनुप्रयोगों आदि में अत्याधुनिक समाधान प्रदान करना शामिल है। इसने 6जी के उपयोग पर अन्वेषणात्मक अनुसंधान भी शुरू किया है जो भारत को अगली पीढ़ी के संपर्क में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से मेल खाता है।

सी-डॉट बोर्ड के सदस्यों के साथ मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल और मॉरीशस दूरसंचार के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष श्री शरत दत्त लालाह

सी-डॉट बोर्ड के सदस्यों के साथ मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल और मॉरीशस दूरसंचार के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष श्री शरत दत्त लालाह को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

डॉ. राजकुमार उपाध्याय मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

डॉ. राजकुमार उपाध्याय, मॉरीशस टेलीकॉम के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष, श्री शरत दत्त लालाह को सी-डॉट समाधानों की जानकारी प्रदान करते हुए

डॉ. राजकुमार उपाध्याय, मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री, महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल और मॉरीशस टेलीकॉम के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष, श्री शरत दत्त लालाह को सी-डॉट के ईएसओसी समाधान से अवगत कराते हुए

डॉ. राजकुमार उपाध्याय, मॉरीशस के सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नवाचार मंत्री, महामहिम डॉ. अविनाश रामतोहुल और मॉरीशस टेलीकॉम के जी.ओ.एस.के. अध्यक्ष, श्री शरत दत्त लालाह को सी-डॉट के आपदा प्रबंधन समाधान की जानकारी प्रदान करते हुए

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर तीसरे दौर की वार्ता क्वीन्सटाउन में संपन्न

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के दृष्टिकोण से प्रेरित एफटीए वार्ता

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-न्यूजीलैंड व्यापार में 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज; एफटीए से आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद

(जीएनएस)।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर तीसरे दौर की वार्ता 19 सितंबर, 2025 को क्वीन्सटाउन, न्यूजीलैंड में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान चर्चा से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और संतुलित एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर शीघ्र निष्कर्ष निकालने की दिशा में काम करने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री माननीय क्रिस्टोफर लक्सन के दृष्टिकोण से प्रेरित, वाताओं में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को गहरा करने का साझा संकल्प परिलक्षित हुआ। एफटीए औपचारिक रूप से 16 मार्च, 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री टॉड मैक्ले की बैठक के दौरान शुरू किया गया।

15 से 19 सितंबर, 2025 तक आयोजित तीसरे दौर में समझौते के सभी क्षेत्रों पर रचनात्मक चर्चा हुई। कई अध्याय पूरे हुए और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

वित्त वर्ष 2024-25 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। प्रस्तावित एफटीए से व्यापार प्रवाह को और बढ़ावा मिलने, निवेश संबंधों को बढ़ावा मिलने, आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने और दोनों देशों में व्यवसायों के लिए विश्वसनीय ढांचा तैयार होने की उम्मीद है।

दोनों पक्षों ने अंतर-सत्रीय वाताओं के माध्यम से गति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। आमने-सामने की वार्ता का अगला दौर 13-14 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

Ministry of Ports, Shipping and Waterways
Government of India
Government of Gujarat
Gujarat Maritime Board

भारतीय मेरीटाइम सेक्टर

विकास की लहरें, विश्वास का आधार

समुद्र से समृद्धि

मेरीटाइम सेक्टर का कायाकल्प

माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के

कर-कमलों से

भारत सरकार एवं गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास।

₹७,६७०+ करोड़

(MoPSW, भारत सरकार) की परियोजनाएँ

भारत के समुद्री तटीय विकास के नए द्वार

- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण की ३ परियोजनाएँ:** व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर टर्मिनल (पीपीपी मॉडल), ऊर्जा आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल, और बंदरगाह संचालन को अधिक कुशल बनाने हेतु बर्थ मॉर्डनाइजेशन
- **पारादीप पोर्ट प्राधिकरण की ४ परियोजनाएँ:** कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए २ नए बर्थ का विकास और २ मौजूदा बर्थ का मशीनीकरण
- **कामराजर पोर्ट लिमिटेड की २ परियोजनाएँ:** सुरक्षित और सतत बंदरगाह संचालन के लिए HSE अनुपालन तथा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना
- **दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण की ११ परियोजनाएँ:** उन्नत निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा के लिए ग्रीन बायो-मीथेनॉल प्लांट, बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ, नया ऑयल जेट्टी, सिविल वर्क्स, और बर्थ अपग्रेडेशन जैसी पहलें जो व्यापार और सतत विकास को मजबूत बनाएंगी।
- **अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ३ परियोजनाएँ:** २ स्थानों पर जहाज मरम्मत सुविधाओं का विकास और एक फ्रेट विलेज की स्थापना, जिससे अंतर्देशीय परिवहन और लॉजिस्टिक्स को गति मिलेगी
- **चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट प्राधिकरण और अंडमान-लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स की १-१ परियोजना:** क्षेत्रीय बंदरगाह सुविधाओं और कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाना

₹२५,९५४+ करोड़

(भारत सरकार एवं गुजरात सरकार) की गुजरात में परियोजनाएँ

सड़कों, अवसंरचना और ऊर्जा से भविष्य की ओर प्रगति की नई राह

- **गुजरात सरकार की १९ परियोजनाएँ:** बेहतर संपर्क के लिए सड़कें, स्वच्छता के लिए सीवेज सिस्टम, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएँ, तटीय सुरक्षा हेतु सीवॉल्स और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पीवी परियोजनाएँ
- **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की २ परियोजनाएँ:** ऊर्जा सुरक्षा के लिए री-गैसीफिकेशन टर्मिनल तथा औद्योगिक उत्पादन को गति देने के लिए एक्रिलिक्स/ऑक्सो अल्कोहल परियोजना
- **नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ३ परियोजनाएँ:** सुरेन्द्रनगर और वडोदरा में २ सौर परियोजनाएँ तथा पीएम-कुसुम फीडर लेवल सोलराइजेशन योजना, जो ग्रामीण विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करेगी
- **कोयला मंत्रालय की ३ परियोजनाएँ:** ३०० मेगावॉट और ६०० मेगावॉट की दो बड़ी सौर परियोजनाएँ तथा ५० मेगावॉट की एक पवन परियोजना, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा
- **विद्युत मंत्रालय की ३ परियोजनाएँ:** खावड़ा सोलर पार्क का ३ क्षेत्रों में विकास, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा
- **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की २ परियोजनाएँ:** इन परियोजनाओं से गुजरात में सड़क संपर्क व आवागमन और बेहतर होगा

गरिमामयी उपस्थिति

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

श्री सर्बानंद सोनोवाल
माननीय केंद्रीय मंत्री
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, भारत

श्री मनसुख मांडविया
माननीय केंद्रीय मंत्री
श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल, भारत

श्री सी. आर. पाटील
माननीय केंद्रीय मंत्री
जल शक्ति, भारत

विशिष्ट अतिथि

श्री शांतनु ठाकुर
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, भारत

श्रीमती निमुबेन जे. बांभणिया
माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, भारत

२० सितंबर २०२५, शनिवार | सुबह ०९:०० बजे | जवाहर मैदान, भावनगर, गुजरात

सीधा प्रसारण : DD News | CMOGuj | CMOGuj | CMOGujarat | CMOGujarat

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा 2025 की तर्ज.पर शुरू की विशेष अभियान 5.0 की तैयारी

स्वच्छता और लंबित मामलों के समय पर निपटान को प्राथमिकता देता है विशेष अभियान 5.0

विशेष अभियान 5.0 डीएआरपीजी दिशानिदेशों के अनुरूप 2 से 31 अक्तूबर 2025 तक सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा

(जीएनएस)।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों का प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए 16 सितंबर 2025 से विशेष अभियान 5.0 के प्रारंभिक चरण की शुरूआत की है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशानिदेशों के अनुरूप 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2025 तक पूरे विभाग में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छता पद्धतियों को संस्थागत बनाना और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना है।

2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2024 तक आयोजित विशेष अभियान 4.0 की उपलब्धियों के आधार पर, डीडीडब्ल्यूएस ने अपने सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यापक गतिविधियाँ संचालित कीं। इस चरण के दौरान, वीआईपी मामलों, आईएमसी मामलों, राज्य सरकार के मामलों, पीएमओ के मामलों, लोक शिकायत और अपील सहित विभिन्न श्रेणियों के मामलों के निपटान में उल्लेखनीय प्रगति हुई। चिन्हित फाइलों की समीक्षा की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1,60,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रगति को डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया गया और अभियान के संदेश को व्यापक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर भी प्रचार किया गया।

विशेष अभियान 4.0 के दौरान प्राप्त की गई गति पूरे वर्ष बनाए रखी गई। उल्लेखनीय उपलब्धियों में शामिल हैं:

- 1 नवंबर 2024 और 31 अगस्त 2025 के बीच 91 वीआईपी मामलों का निपटान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, 7 पीएमओ के मामलों, 14 संसदीय आश्वासन और 24 राज्य सरकार के मामलों का समाधान किया गया।
- इस अवधि के दौरान 8,024 में से 7,771 लोक शिकायतों का निपटारा किया गया, जिसका औसत निपटान समय 13 दिन था।
- इसके अलावा, 1,652 लोक शिकायत अपीलों का भी निपटारा किया गया। अभिलेख प्रबंधन के अंतर्गत, समीक्षा के लिए चिन्हित 90 फाइलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।

विशेष अभियान 5.0 के साथ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और पारदर्शिता, दक्षता एवं नागरिक-केंद्रित शासन की भावना से सार्वजनिक मामलों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह पहल ऐसे समय में की गई है जब विभाग वर्तमान में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान (17 सितंबर - 2 अक्तूबर) का नेतृत्व कर रहा है, जो ग्रामीण भारत के समुदायों को बड़े पैमाने पर श्रमदान गतिविधियों में जुटाता है, और इस बात पर जोर देता है कि स्वच्छता एक संस्थागत और जन-आंदोलन, दोनों ही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 20 सितंबर को भावनगर में आयोजित होगा 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम

प्रधानमंत्री गुजरात को भारत सरकार तथा गुजरात सरकार अधीनस्थ विभागों के 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की भेंट देंगे

भारत सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग तथा वॉटरवेज मंत्रालय अंतर्गत 66 हजार करोड़ रुपए से अधिक के मैरीटाइम-शिप बिल्डिंग एमओयूस का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे

यूएनडब्लूटीओ द्वारा 'बेस्ट टूरिज्म विलेज' के रूप में प्रतिष्ठित कच्छ के धोरडो गाँव का हुआ 100 प्रतिशत सोलराइजेशन

वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी में 5,894 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंडियन ऑयल के एक्रेलिक/ऑक्सो-अल्कोहोल प्रोजेक्ट तथा 4,700 करोड़ रुपए की लागत से छारा बंदरगाह पर निर्मित एचपीएलएनजी एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल का लोकार्पण

गांधीनगर, 19 सितंबर :प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 20 सितंबर, 2025 यानी शनिवार को भावनगर में आयोजित 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। देश की विकास यात्रा को समुद्र से समृद्धि की दिशा में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग तथा वॉटरवेज (बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग) मंत्रालय अंतर्गत 66,025 करोड़ रुपए के एमओयूस का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण करेंगे; जिनमें बंदरगाहों व शिपिंग से संबंधित 21 एमओयू शामिल हैं। इसके साथ ही; प्रधानमंत्री पोर्ट्स, शिपिंग तथा वॉटरवेज मंत्रालय अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए 7,870 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री गुजरात की जनता को भी अनेक विकास कार्यों की भेंट देंगे। वे भारत सरकार व गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों के तहत राज्य की जनता के लिए 26,354 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। इस प्रकार; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विकास कार्यों की भारत की जनता को भेंट देंगे। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग विभाग के मंत्री श्री सबानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि भावनगर में आयोजित कार्यक्रम में श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों के तहत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करने जा रहे हैं। इन विभागों में ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क एवं भवन, शहरी विकास, जल संसाधन एवं जल आपूर्ति तथा मत्स्योद्योग (कृषि) विभाग शामिल हैं।

गुजरात को मिलेगी 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की भेंट

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0 सफलतापूर्वक संपन्न किया एवं विशेष अभियान 5.0 के लिए तैयार

(जीएनएस)।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विशेष अभियान 4.0, प्रभावशाली परिणामों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। इसमें शासन—प्रशासन में भारत सरकार के पारदर्शिता, दक्षता एवं स्वच्छता के सिद्धांतों पालन किया गया है। अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लगातार ऐसी गतिविधियाँ चलाईं जिनसे जन शिकायतों के त्वरित निपटारे, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्यालय के स्थान के अधिकतम उपयोग एवं जन सेवा निस्तारण को बढ़ाने में सफलता मिली है। विशेष अभियान 4.0 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां रिकार्ड की गई हैं जिनमें शामिल हैं— सांसदों द्वारा भेजे गए 37 संदर्भों का सफल निस्तारण, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त 25 मामले, 02 संसदीय आश्वासन, दो अंतर मंत्रालयीन संदर्भ (मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव), 268 जन शिकायत एवं जन शिकायतों पर अपीलों का 100 प्रतिशत निस्तारण।

इनके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण स्वच्छता एवं रिकॉर्ड प्रबंध उपायों को भी लागू किया है। मंत्रालय एवं इसके 11 संस्थानों द्वारा 74 स्वच्छता मुहिम चलाई गईं जिसके परिणामस्वरूप 2000 वर्गफीट कार्यालय की जगह खाली प्राप्त हुई। इसके बेहतर रिकॉर्ड प्रबंध तथा कार्यालय अनुकूलन जैसे उपाय किए गए। अभियान के दौरान

कबाड़ के निस्तारण द्वारा मंत्रालय ने 6.25 लाख रूपए राजस्व भी अर्जित किया। पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत अनेक नई गतिविधियां करने को सन्नद्ध है। यह गतिविधियां 02 अक्तूबर, 2025 से 31 अक्तूबर, 2025 तक मंत्रालय के सभी संस्थानों द्वारा प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग के निकट समन्वय सहित की जाएंगी। इस बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री डी. सेंथिल पांडियन ने मंत्रालय के सभी संस्थानों के संपर्क अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 5.0 एवं स्वच्छता ही सेवा मुहिम 2025 का खाका बनाने के लिए वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री पांडियन ने अग्रसक्रिय प्रशासन के महत्व को रेखांकित किया। उनका कहना था कि हाथों हाथ रिकॉर्ड प्रबंध, स्वच्छता एवं जन सेवा निस्तारण प्रणाली में सुधार लाना ही पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन की बुनियाद हैं। आगामी विशेष अभियान 5.0 में कम्प्यूटरों, लैपटॉप एवं प्रिंटरों के लिए विशेष ई—कचरा निस्तारण अभियान पर ध्यान दिया जाएगा। यह अभियान 2022 के ई—कचरा प्रबंध नियमों के तहत होगा। इसके साथ ही संसदीय आश्वासनों, मंत्रिमंडलीय नोट एवं राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित मामलों के त्वरित अनुपालन, सभी कार्यालयों एवं फील्ड कार्यालयों में सतत सफाई अभियान, रिकॉर्ड प्रबंध प्रणाली को सुव्यवस्थित करने एवं उपलब्ध स्थान के अधिकतम प्रयोग से बेहतर दक्षता पाने एवं सीपीग्राम्स के माध्यम से जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया जाएगा।

स्वच्छता ही सेवा 2025 के सिलसिले में ही 'स्वच्छोत्सव' के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं इसके संस्थान सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, पर्यानुकूल समारोह,स्वास्त्य जाचं शिविरों एवं स्वच्छ एवं स्वस्था भारत के लिए समुदाय संचालित मुहिम भी आयोजित करेंगे।

विशेष अभियान 4.0 के सफल समापन एवं आगामी विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा स्वच्छ, दक्ष एवं नागरिकोन्मूख संस्थाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दौराया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा यह संकल्प भारत सरकार की प्रशासनिक सरलता अपनाने एवं स्वच्छ भारत संबंधी दृष्टि के अनुरूप किया जा रहा है।

श्री डी. सेंथिल पांडियन,पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव (बायें) अपने मंत्रालय के सभी संस्थानों के संपर्क अधिकारियों के साथ विशेष अभियान5.0 एवं स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का खाका बनाने संबंधी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, इंक. (आर एंड आई) ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को बीबीबी+ (स्थिर) तक अपग्रेड किया

(जीएनएस)।

यह इस वर्ष किसी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत का तीसरा ऐसा अपग्रेड है, इससे पहले अगस्त 2025 में एसएंडपी द्वारा 'बीबीबी' (बीबीबी- से) और मई 2025 में मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस द्वारा 'बीबीबी' (बीबीबी (निम्न) से) में अपग्रेड किया गया

पांच महीनों में भारत के लिए तीन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भारत के मजबूत और लचीले वृहद आर्थिक बुनियादी कारकों और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए बढ़ती वैश्विक मान्यता को दशार्ते हैं और व्याप्त वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं में वैश्विक विश्वास को रेखांकित करते हैं

(जीएनएस)।

भारत सरकार जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, इंक. (आर एंड आई) द्वारा भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी' से बढ़ाकर 'बीबीबी+' करने और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए "स्टेबल" आउटलुक बरकरार रखने के निर्णय का स्वागत करती है।

यह इस वर्ष किसी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया गया तीसरा अपग्रेड है, इससे पहले एसएंडपी ने अगस्त 2025 में 'बीबीबी' (बीबीबी-से) और मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस ने मई 2025 में 'बीबीबी' (बीबीबी (निम्न) से) अपग्रेड किया था, जिससे विश्व में सर्वाधिक गतिशील और लचीली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि हुई है।

आज प्रकाशित आर एंड आई की भारत सॉवरेन रेटिंग समीक्षा के अनुसार, रेटिंग में यह अपग्रेड दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत की स्थिति द्वारा समर्थित है, जो इसके जनसांख्यिकीय लाभांश, मजबूत घरेलू मांग और सुदृढ़ सरकारी नीतियों पर आधारित है। आर एंड आई ने अपनी रिपोर्ट में सरकार द्वारा राजकोषीय समेकन में प्रगति को मान्यता दी है, जो कि उच्च विकास के साथ-साथ कर राजस्व में वृद्धि और सब्सिडी के युक्तिकरण, और ऋण के प्रबंधनीय स्तर द्वारा संचालित है। यह भारत की मजबूत बा' स्थिरता पर भी प्रकाश डालता है, जो मामूली चालू खाता घाटा, सेवाओं और प्रेषणों (रेमिटेंस) में स्थिर अधिशेष, कम बा' ऋण-से-जीडीपी अनुपात और पर्याप्त विदेशी मुद्रा कवर में परिलक्षित होती है।

एजेंसी ने यह भी कहा कि वित्तीय प्रणाली से जुड़े जोखिम सीमित हैं। एजेंसी ने अपने वक्तव्य में कहा, "सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है, लेकिन मजबूत घरेलू मांग और सब्सिडी में कटौती से कर राजस्व में वृद्धि के कारण वह राजकोषीय घाटे को कम करने में सफल रही है।" एजेंसी ने अमेरिका द्वारा हाल ही में टैरिफ में की गई वृद्धि को एक जोखिम कारक माना, हालांकि, उसने यह भी माना कि भारत की अमेरिकी निर्यात पर सीमित निर्भरता और घरेलू मांग-आधारित विकास मॉडल इस प्रभाव को नियंत्रित कर सकते हैं। एजेंसी ने यह भी कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से राजस्व में कमी आएगी, लेकिन निजी उपभोग को बढ़ावा देकर इस नकारात्मक प्रभाव की कुछ हद तक भरपाई की जा सकेगी।

एजेंसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रशासन की नीतियों की भी प्रशंसा की, जिनका मुख्य उद्देश्य विदेशी विनिमार्ताओं को भारत की ओर आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना, कारोबारी माहौल में सुधार के लिए कानूनी ढांचे को संस्थागत बनाना, ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

यह इस वर्ष एसएंडपी, मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस और आरएंडआई द्वारा भारत को प्राप्त तीसरा क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड है और यह भारत के मजबूत तथा लचीले वृहद-आर्थिक बुनियादी कारकों और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए बढ़ती वैश्विक मान्यता को दशार्ता है। यह व्याप्त वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं में वैश्विक विश्वास को भी रेखांकित करता है। भारत सरकार राजकोषीय विवेक और वृहद-आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ समावेशी, उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

तीव्र गश्ती पोत आईसीजीएस अदम्य को पारादीप बंदरगाह पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया

(जीएनएस)।

भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) 'अदम्य' को 19 सितंबर, 2025 को ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। यह अदम्य श्रेणी के आठ तीव्र गश्ती पोत (एफपीवी) श्रृंखला के पहले जहाज के रूप में शामिल किया गया है। इस 51 मीटर लंबे अत्याधुनिक पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अदम्य जहाज 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' का एक उपयुक्त उदाहरण है, जिससे देश के समुद्री सुरक्षा सामर्थ्य में और मजबूती आएगी।

आईसीजीएस अदम्य का औपचारिक कमीशन रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (एएफ एवं नीति) श्री सत्यजीत मोहंती ने किया। इस अवसर पर मुख्यालय ईस्टर्न सीबोर्ड के चीफ ऑफ स्टाफ इंस्पेक्टर जनरल योगिंदर ढाका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया।

यह पोत ओडिशा के पारादीप में तैनात रहेगा। इसका परिचालन व प्रशासनिक नियंत्रण कमांडर, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र (पूर्वोत्तर) के अधीन आईसीजी जिला मुख्यालय संख्या-7 (ओडिशा) द्वारा किया जाएगा। 'अदम्य' शब्द का अर्थ 'अविजेय' होता है, यह भारतीय तटरक्षक बल की उस अटूट इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा हेतु सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। आईसीजीएस अदम्य पर पांच अधिकारी और 34 कर्मी नियुक्त रहेंगे। यह पोत न केवल समुद्री क्षेत्रों की सतत निगरानी करेगा, बल्कि तटरक्षक बल के चार्टर में निर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करेगा, जिससे भारत के समुद्री हितों की सशक्त एवं प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इस पोत का भार विस्थापन लगभग 320 टन है और यह दो 3000 किलोवाट के डीजल इंजनों से संचालित होता है, जिसके चलते यह 28 नॉट की अधिकतम गति और सामान्य रफ्तार पर 1500 नॉट की स्थिरता प्राप्त करता है। आईसीजीएस अदम्य पहला ऐसा जहाज है, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित दो नियंत्रणीय पिच प्रोपेलर और गियरबॉक्स से सुसज्जित किया गया है। यह तकनीक इस पोत के लिए समुद्र में उत्कृष्ट गतिशीलता, अधिक परिचालन लचीलापन और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करती है। इसके हथियारों में एक 30 मिलीमीटर सीआरएन-91 गन और दो 12.7 मिलीमीटर स्थिर, रिमोट-नियंत्रित मशीन गन शामिल हैं, जिन्हें आधुनिक नियंत्रण प्रणालियों के साथ संचालित किया जाता है। इस पोत में एकीकृत ब्रिज प्रणाली, अनिवार्य प्लेटफार्म प्रबंधन सुविधा, स्वचालित ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और उन्नत परिचालन दक्षता एवं स्वचालन की सुविधाएं भी मौजूद हैं।

हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की धुरी है, जिससे सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्रालय पहली बार वर्ष 2024-25 के 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की धुरी बताया जो सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। हिंदी दिवस पर अपने संदेश में श्री सिंह ने कहा कि 'हिंदी दिवस उस सांस्कृतिक शक्ति को नमन करने का अवसर है जिसने हमारे विविध और विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बाँध रखा है। उन्होंने कहा कि रक्षा, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति हर क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता उपयोग न केवल प्रशासन को पारदर्शी बनाता है, बल्कि यह आम नागरिक की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है ।

श्री राजनाथ सिंह ने सभी भारतीयों से यह संकल्प लेने का आग्रह किया कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को केवल संवाद की भाषा तक सीमित न रखकर, विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों तक विस्तारित किया जाए।

उन्होंने लोगों से हिन्दी को सहज संवाद का माध्यम बनाने और क्षेत्रीय भाषाओं के सरल एवं प्रचलित शब्दों का समुचित उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कार्यालयों के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड समर्थित सॉफ़्टवेयर और द्विभाषी कार्य करने की सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर जोर दिया । मंत्रालय की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' मंत्रालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता का परिणाम है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा बनाने की दिशा में सतत प्रयास करें।

रक्षा मंत्रालय के सभी कार्यालयों में दिनांक 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है।

विकसित भारत @2047: छावनी बोर्डों के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु 'मंथन 2025' नामक दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ

मुख्य बिंदुओं में 2030 तक कार्बन-न्यूट्रल छावनी, 2035 तक स्मार्ट छावनी, समावेशी विकास, जीवन में आसानी एवं व्यापार करने में सुगमता और डिजिटल प्रथम सेवा वितरण का लक्ष्य शामिल हैं

(जीएनएस)।

सरकार के 'विकसित भारत @2047' विजन के अनुरूप, छावनी बोर्डों के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु भारतीय रक्षा संपदा सेवा (आईडीईएस) अधिकारियों का दो दिवसीय सम्मेलन मंथन 2025 19 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 18 सितंबर को उद्घाटन सत्र में अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों से छावनी बोर्डों को स्मार्ट, हरित एवं टिकाऊ शहरी इकोसिस्टम में रूपांतरित करने के लिए प्रेरित किया और वर्ष 2035 तक इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ठोस

प्रयासों का आ'ान किया।

भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री मनोज जोशी, भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमानी (वर्चुअल माध्यम से) और भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री सुबीर मलिक जैसे प्रतिष्ठित मुख्य वक्ताओं की बहुमूल्य अंतर्दृष्टि ने अधिकारियों को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया।

दो दिवसीय सम्मेलन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. 2030 तक कार्बन न्यूट्रल छावनी

नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड, रूफटॉप सौर ऊर्जा, बायो-गैस एवं अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करना;

ईवी चार्जिंग हब, हरित परिवहन व बड़े पैमाने पर वनरोपण को प्रोत्साहित करना;

कार्बन ऑडिट तथा वार्षिक स्थिरता रिपोर्टिंग को संस्थागत बनाना।

2. 2035 तक स्मार्ट छावनी

डिजिटल रूप से सक्षम, हरित और नागरिक-अनुकूल इकोसिस्टम का निर्माण करना

स्मार्ट पावर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित निगरानी, ई-मोबिलिटी और जल पुनर्चक्रण का एकीकरण करना

आधुनिक सुविधाओं के साथ विरासत संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना।

3. समावेशी विकास और जीवन यापन में आसानी

गरीबों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

बाधा-मुक्त बुनियादी ढांचे एवं समावेशी सामाजिक सुविधाओं का विकास किया जाए।

छावनियों को करुणामय और उत्तरदायी शासन का आदर्श स्वरूप बनाया जा सके।

संस्कृति मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान 2025 का शुभारंभ

(जीएनएस)।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के नेतृत्व में "स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस), 2025" अभियान, संस्कृति मंत्रालय और उसके सभी संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जा रहा है । इस वर्ष का विषय "स्वच्छोत्सव" है, जो उत्सवों की भावना को स्वच्छता की ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ता है ।

मंत्रालय ने एसएचएस के सभी 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों को कवर करते हुए गतिविधियों का आयोजन करने की योजना बनाई है, जैसे नुक्कड़ नाटक, निबंध/पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, अपशिष्ट से कला कार्यशाला, श्रमदान और वृक्षारोपण अभियान। दिल्ली के

पुराना किला परिसर में बड़े पैमाने पर श्रमदान और वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के लिए इस मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा " एक दिन, एक घंटा, एक साथ" की एक अनूठी पहल की जाएगी। सफाई मित्रों और ऐसे अन्य श्रमिकों को स्वच्छता किट वितरित की जाएंगी। स्वच्छता और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए कार्यालय परिसर के आसपास सड़क विक्रेताओं के लिए जागरूकता अभियान भी इस मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा, स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी के मूल्यों को फैलाने में

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मण्डल

ई-निविदा सूचना संख्याः 05 2025-26 दिनांकः 18/09/2025

ट्रैक मशीनों में अमुख्य मरम्मत कार्य

निविदा सं. CWMCPOHADI2025-26-05

कार्य का नामः CPOH अहमदाबाद अंतर्गत POH के दौरान ट्रैक मशीनों में अमुख्य मरम्मत कार्य।

अनुमानित NIT की लागतः ₹ 3,91,22,551.55/-

ईएमडी शुल्क रु. मेंः ₹ 3,45,700.00/-

निविदा बंद होने एवं खुलने की तारीख एवं समयः दिनांकः 15/10/2025 को 11:00 बजे एवं दिनांक 15/10/2025 को 11:15 बजे

ADI-165

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: x.com/WesternRly